PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Fri, 02 Jun 2017, Page 16
Width: 11.33 cms, Height: 21.69 cms, a4, Ref: 37.2017-06-02.159

जीएसटी पर बेसुरा राग

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते तीन साल में आर्थिक मोर्चे पर हासिल उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए यह जो स्पष्ट किया कि केवल नोटबंदी के कारण जीडीपी में गिरावट नहीं आई वह बहुत हद तक सही है। यह एक तथ्य है कि आज किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की दशा-दिशा वैश्विक कारणों से भी प्रभावित होती है। यह भी एक सच्चाई है कि पिछले तीन साल में भारतीय अर्थव्यवस्था की साख बढ़ी है। मोदी सरकार ने तमाम ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे वैश्विक निवेशकों को यह संदेश गया है कि भारत आर्थिक मोर्चे पर मजबूत हो रहा है। ऐसे कदमों में सबसे महत्वपूर्ण है वस्तु एवं सेवाकर अर्थात जीएसटी का अमल में आना। चूंकि वित्त मंत्री ने एक जुलाई से जीएसटी के अमल का भरोसा दिलाते हुए टैक्स दरों के मामले में पर्याप्त अध्ययन के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने को कहा इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि दरों में कटौती की मांग को लेकर आंदोलन की मुद्रा अपनाने से बचा जाए। यह ध्यान रहे कि किसी भी नई व्यवस्था के अमल में प्रारंभ में कुछ कठिनाई आती ही है। यह ठीक नहीं कि जब केंद्र एवं राज्यों के सरकारी अमले के साथ उद्योग-व्यापार जगत जीएसटी के अमल के लिए अपने-अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है तब पश्चिम बंगाल सरकार संकीर्ण रवैये का प्रदर्शन कर रही है। पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का यह कहना असहयोग भरे रवैये के अलावा और कुछ नहीं कि उनके राज्य के लिए जीएसटी को मौजूदा स्वरूप में लागू करना संभव नहीं। ध्यान रहे कि इस मौजूदा स्वरूप को जिस परिषद ने तय किया है उसका हिस्सा बंगाल भी है।

क्या इससे बड़ी विडंबना और कोई हो सकती है कि अर्थशास्त्री के तौर पर पहचान रखने वाले अमित मित्रा नारेबाजी की राजनीति में माहिर नेता की तरह बोल रहे हैं? इसमें दो राय नहीं कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए विवश हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि उनका बयान जीएसटी काउंसिल के रूप में बनी संघीय व्यवस्था पर चोट करने वाला है। आखिर जो लोग संघीय व्यवस्था का खुद ही हिस्सा हों वे उसके विरोध में कैसे खड़े हो सकते हैं? पश्चिम बंगाल सरकार किस तरह जानबूझकर जीएसटी की राह में रोड़ा अटका रही है, इसका पता इससे चलता है कि जैसी अनावश्यक आपत्तियां उसके वित्त मंत्री उठा रहे हैं वैसी अन्य किसी राज्य के वित्त मंत्री की ओर से सुनने को नहीं मिली हैं। यह पहली बार नहीं जब ममता बनर्जी राष्ट्रीय महत्व के किसी मसले पर अलग राग अलापने के साथ केंद्र सरकार से असहयोग कर रही हों। यह किसी से छिपा नहीं कि वह अंतरराष्ट्रीय मसलों और खास तौर से बांग्लादेश से संबंधों के मामले में भी बाधक बनती रही हैं। राष्ट्रीय हितों की कीमत पर संकीर्ण राजनीतिक हितों को जरूरत से ज्यादा तूल दिया जाना एक तरह की जनविरोधी राजनीति है। जब सभी यह मान रहे हैं कि अकेले जीएसटी पर अमल से जीडीपी में डेढ़ से दो प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है तब फिर किसी को भी यह शोभा नहीं देता कि वह इस नई व्यवस्था की राह में अड़ंगा डाले।